भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 778

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र में सड़क निर्माण

778. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003 में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के साथ हुए समझौते के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के उत्तरी भाग में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर सहमति व्यक्त की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पन्द्रह वर्षों के दौरान इन सड़क निर्माणों के लिए संस्वीकृत राशि और जारी की गई निधि सहित उक्त सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त समझौते के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में बाणासुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त निर्माण के लिए संस्वीकृत/जारी की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से वर्ष 2003 में हस्ताक्षरित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) समझौते में सड़क निर्माण से संबंधित दो कार्यों नामतः (i) कोइलामोइला, अमगुरी आदि को जिले के शेष भाग से जोड़ने के लिए आई नदी पर एक पुल का निर्माण; और (ii) सीमा से सटे दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए भारत-भूटान सीमा पर जामदुआर से भैरबकुंडा तक राजमार्ग के निर्माण का उल्लेख है। सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचएस) के विकास और अनुरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उक्त सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं। इसके अलावा, सरकार अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विगत 15 वर्षों के दौरान 1,857 करोड़ रुपये की लागत से 118 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया है, और इसके अतिरिक्त, असम राज्य में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र से गुजरने वाले 614 करोड़ रुपये की लागत से 28 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

*****